S. No.	District	No. of Warehouses of CWC	Total storage capacity (in tonnes)
1	2	3	4
1.	Amritsar	4	81521
2.	Bhatinda	2	26347
3.	Faridkot	6	137302
4.	Ferozpur	5	68034
5.	Gurdaspur	3	69367
6.	Hoshiarpur	2	20000
7.	Jullandhar	1	14900
8.	Ludhiana	1	19713
9.	Patiala	3	141884
10.	Rupnagar (Ropar)	1	8138
11.	Sangrur	1	92987
	TOTAL:	29	6,80,193

Notices served by ESTS authorities for recovery of damages

2098. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:
SHRI JAGIR SINGH DARD:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government is aware that the Employees State Insurance Scheme (ESIS) authorities are harassing the employers by sending them notices for recovery of damages as old as 30 years for which no notice was given earlier; and

(b) in what manner this problem will be sorted out?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) The provisions relating to levy of damages for delayed payments of ESI contributions were introduced in 1975 and made effective from 1.9.1975. The damages are levied on the defaulting employer for delayed payment of contribution after the contribution is paid by the employer, on the basis of the record maintained in the office regarding the dates of payment by the employer. Before lavy of damages the employer is given an opportunity to explain why the damages on the delayed payment of contribution be not levied. The employer is also given an opportunity of being heard before damages are levied. In all cases where the contribution is paid late by the employer. He/she is aware of the delayed payment. Hence it is for the employer to keep the relevant record.

8th Five Year Plan progress in Kalahandi district of Orissa

2099. SHRI BASANT KUMAR DAS: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether any assessment has been made regarding the progress of the Eighth Five Year Plan in Kalahandi district in Orissa;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether any programme made earlier than the Eighth Five Year Plan is

pending completion and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAV A): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

BICP recommendations with regard to sugar industry

2100. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the Centre has examined the report of Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) to facilitate the reworking of the Licencing Policy for sugar sector;

(b) what are the salient features in the BICP recommendations in regard to fixing of free sale quota in high recovery areas and exemption of levy on expanded capacity; and

(c) the reaction of Indian Sugar Mills Association (ISMA) and National Federation of Cooperative Sugar Factories in this regard?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) Ministry of Food has recently received a Report on Sugar Incentive Scheme from the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) for grant of incentives for new and expansion projects licensed/to be licensed during the period from 01-04-1994 to 31-03-1997. The Report is under examination.

विदेशी क्रेताओं को घटिया माल की आपूर्ति

2101. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1994-95 के दौरान घटिया स्तर की वस्तुओं की आपूर्ति किए जाने के संबंध में क्रेताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(क) शिकायतें मुख्य रूप से सहमत उत्पाद विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने और खाद्य मदों जल्दी खराब होने वाली मदों में खराबी अथवा प्रदूषण के बारे में थी।

(ख) गुणवत्ता शिकायतों संबंधी क्षेत्रीय स्थायी समितियों का गठन अहमदाबाद, बंबई, बंगलौर, कलकत्ता, कोचीन दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना और मद्रास में किया गया हैं जो इस प्रकार की शिकायतों की जांच करती हैं। इन समितियों ने वर्ष 1994-95 में इस प्रकार की 66 शिकायतों का निपटान किया। वर्ष 1994-95 के दौरान 20 निर्यातकों के विरूद्व विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की गई और 9 मामलों में वित्तीय दण्ड वर्जन आयातक-निर्यातक कोड संख्या का निरसन, आदि की कार्यवाहियों के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं।

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

2102. **श्री मूलचन्द मीणा** :

श्री अजीज जोगी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का विचार हैं;

(ख) इस विशेष योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के बाद अब तक कितनी महिलाओं को रोजगार दिया जा चुका हैं; और

(ग) सरकार चालू वर्ष के दौरान इन प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार देने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के खोले जाने की संख्या निम्नलिखित हैं :- आन्ध्र प्रदेश-13, असम-3, गुजरात-4 , हरियाणा-5, केरल-5, मध्य प्रदेश-10, उत्तर प्रदेश-9